

अध्याय 16: दलीय प्रणाली, गठबंधन राजनीति, क्षेत्रवाद, महिला प्रतिनिधित्व एवं AI-राजनीति — शॉर्ट नोट्स

1. भारत में दलीय प्रणाली का ऐतिहासिक विकास (Party System)

कालखंड / दौर	दलीय प्रणाली का स्वरूप	प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं एवं प्रभाव
1947–1967	एकदलीय प्रभुत्व का दौर	कांग्रेस का केंद्र व राज्यों में निर्बाध शासन; रजनी कोठारी ने इसे 'कांग्रेस प्रणाली (Congress System)' का नाम दिया
1967–1989	बहुदलीय प्रणाली का उदय	1967 में 9 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सविद सरकारें; 1977 में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी मोरारजी देसाई सरकार
1989–2014	गठबंधन राजनीति का दौर	खंडित जनादेश; किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं; राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, (NDA) एवं (UPA) गठबंधन सरकारें
2014 से वर्तमान	एक-प्रमुख दल + गठबंधन दौर	भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत; राजग (NDA) बनाम विपक्षी गठबंधन (INDIA) के बीच द्वि-ध्रुवीय चुनावी मुकाबला

2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल मान्यता के विधिक मानदंड

मान्यता का स्तर	निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 की विहित शर्तें (कोई 1 पूर्ण हो)
राष्ट्रीय दल (National Party) — शर्त 1	लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत + कम से कम 4 लोकसभा सीटें
राष्ट्रीय दल — शर्त 2	लोकसभा की कुल सीटों का न्यूनतम 2% (वर्तमान में 11 सीटें) कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से जीतना अनिवार्य
राष्ट्रीय दल — शर्त 3	दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल (State Party) के रूप में विधिक मान्यता प्राप्त हो
वर्तमान 6 राष्ट्रीय दल	1. भारतीय जनता पार्टी (BJP), 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), 3. आम आदमी पार्टी (AAP), 4. बहुजन समाज पार्टी (BSP), 5. माकपा (CPI-M), 6. नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP)
राज्य स्तरीय दल (State Party)	विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% + 2 सीटें, अथवा लोकसभा में राज्य के कुल मतों का 6% + 1 सीट, अथवा विधानसभा की कुल सीटों का 3% या न्यूनतम 3 सीटें

3. गठबंधन राजनीति (Coalition Politics): आयाम, लाभ एवं चुनौतियां

पहलू / आयाम	प्रशासनिक व राजनीतिक विश्लेषण एवं भारतीय संदर्भ
अवधारणा व स्वरूप	जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिले, तब दो या अधिक दल मिलकर 'साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP)' पर सरकार बनाते हैं
गठबंधन के प्रकार	1. चुनाव-पूर्व गठबंधन (Pre-Poll Alliance — अधिक स्थायी, जैसे NDA/INDIA), 2. चुनाव-पश्चात गठबंधन (Post-Poll Alliance — सत्ता केंद्रित व अस्थिर)
सकारात्मक पक्ष	निरंकुशता पर रोक; क्षेत्रीय आकांक्षाओं व विविध सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व; संकीर्ण नीतियों के बजाय व्यापक सर्वसम्मति को बढ़ावा
नकारात्मक पक्ष	सरकार के स्थायित्व पर निरंतर संकट; छोटे दलों द्वारा 'सौदेबाजी की राजनीति (Blackmail Politics)'; राष्ट्रीय विदेश/सुरक्षा नीति में दृढ़ता का अभाव

4. क्षेत्रवाद (Regionalism) एवं प्रमुख क्षेत्रीय दल

कारक / आयाम	क्षेत्रवाद के प्रेरक कारक एवं विधिक-राजनीतिक प्रभाव
भाषाई अस्मिता	भाषा आधारित उप-राष्ट्रीय पहचान; 1953 आंध्र प्रदेश गठन से शुरुआत; दक्षिण भारत में भाषा संरक्षण की प्रबल मांग
आर्थिक व क्षेत्रीय असंतुलन	कतिपय राज्यों में औद्योगीकरण व बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन; वित्तीय संसाधनों व केंद्रीय कर हस्तांतरण में विषमता
सांस्कृतिक विशिष्टता	पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय स्वायत्तता, स्थानीय रीति-रिवाजों व आंतरिक रेखा परमिट (ILP) जैसी विशेष सुरक्षा की मांग
प्रमुख क्षेत्रीय दल	द्रमुक (DMK) व अन्नाद्रमुक (तमिलनाडु), तृणमूल कांग्रेस (TMC — प. बंगाल), बीजद (ओडिशा), तेदेपा/(YSRCP) (आंध्र प्रदेश), सपा (उ.प्र.), शिवसेना/राकांपा (महाराष्ट्र)

दलीय व्यवस्था का सार: रजनी कोठारी के अनुसार 'कांग्रेस प्रणाली' केवल एक दल का शासन नहीं थी, बल्कि एक बहु-आयामी छतरी (Umbrella Organization) थी जिसमें विभिन्न गुट आम सहमति से कार्य करते थे। 1989 के बाद गठबंधन संघवाद ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, समावेशी और संघीय चरित्र प्रदान किया है।

5. पहचान-राजनीति (Identity Politics): आयाम एवं प्रभाव

पहचान का आधार	राजनीतिक लाभबंदी की कार्यप्रणाली एवं चुनावी प्रभाव
जातीय गोलबंदी	जातिगत पहचान पर आधारित दलों का गठन; टिकट वितरण व मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता
धार्मिक ध्रुवीकरण	धार्मिक प्रतीकों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक विमर्श का चुनावी लाभ हेतु राजनीतिक उपयोग
क्षेत्रीय व भाषाई पहचान	स्थानीय बनाम बाहरी (Sons of Soil) का नारा; स्थानीय युवाओं हेतु नौकरियों में आरक्षण की मांग
सकारात्मक पक्ष	ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों (SC, ST, OBC) को राजनीतिक मंच व नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी
नकारात्मक पक्ष	विकास एवं सुशासन के वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा; समाज में स्थायी कटुता व ध्रुवीकरण का जोखिम

6. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम

स्तर / कानून	प्रतिनिधित्व की स्थिति एवं प्रमुख वैधानिक प्रावधान
स्थानीय स्तर (पंचायती राज)	73वें व 74वें संशोधन 1992 द्वारा न्यूनतम 33% आरक्षण; राजस्थान सहित 20+ राज्यों में 50% महिला आरक्षण लागू
18वीं लोकसभा (2024)	संसद में केवल 74 महिला सांसद (कुल 543 का 13.6%); 17वीं लोकसभा (14.4%) की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व में गिरावट
106वां संशोधन अधिनियम 2023	नारी शक्ति वंदन अधिनियम (128वां विधेयक): लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित
लागू होने की पूर्व-शर्त	यह अधिनियम तुरंत प्रभावी नहीं हुआ है; अगली जनगणना (Census) संपन्न होने तथा उसके आधार पर परिसीमन (Delimitation) के बाद लागू होगा
आरक्षण की अवधि	लागू होने की तिथि से प्रारंभिक 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा; संसद कानून द्वारा इसकी अवधि आगे बढ़ा सकती है; SC/ST सीटों में 33% उप-आरक्षण

7. चुनावों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग: 2024 लोकसभा चुनाव

तकनीकी नवाचार	चुनावी प्रचार में उपयोग एवं कार्यप्रणाली (AI in Politics)
AI आवाज-क्लोनिंग	दिवंगत अथवा वरिष्ठ राजनेताओं की मूल आवाज का क्लोन बनाकर जन-संपर्क व डिजिटल प्रचार संदेश तैयार करना
बहुभाषी AI अवतार	नेता द्वारा दिए गए मूल हिंदी/अंग्रेजी भाषणों का क्षेत्रीय भाषाओं में स्वचालित रूपांतरण व सिक्रोनाइजेशन
माइक्रो-टारगेटिंग	बिग डेटा एनालिटिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा मतदाताओं के व्यवहार के अनुरूप व्यक्तिगत लक्षित प्रचार संदेश
डीपफेक वीडियो (Deepfakes)	डीप लर्निंग तकनीक से राजनीतिक नेताओं के फर्जी, भ्रामक व उत्तेजक वीडियो/ऑडियो बनाकर चुनावी विमर्श को प्रभावित करना

8. चुनावी शुचिता एवं AI नियमन: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देश

नियामक क्षेत्र	विधिक प्रावधान एवं आयोग के दिशा-निर्देश (ECI Guidelines)
सिंथेटिक सामग्री लेबलिंग	राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को AI-जनित या विकृत सामग्री (Synthetic Media) पर स्पष्ट लेबल/डिस्क्लेमर लगाना अनिवार्य
3 घंटे में निष्कासन	सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediaries) को शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर भ्रामक डीपफेक सामग्री हटाने का आदेश
विधिक दंडात्मक कार्रवाई	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) की धारा 66D, कॉपीराइट कानून एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडात्मक कार्रवाई
सत्यापित संचार व्यवस्था	गलत सूचना (Misinformation) से निपटने हेतु आयोग द्वारा 'मिथक बनाम यथार्थ (Myth vs Reality)' पोर्टल का संचालन

लोकतांत्रिक विकास का सार: दलीय बहुलता और तकनीकी नवाचार के युग में भारतीय लोकतंत्र पहचान की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन और विकास के एजेंडे पर अग्रसर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं की विधायी भागीदारी तथा AI के युग में चुनावी शुचिता की रक्षा ही लोकतांत्रिक परिपक्वता का वास्तविक प्रमाण है।